



**NEERAJ®**

# भारत में राजनीतिक प्रक्रिया

( Political Process in India )

**B.P.S.C.-104**

**B.A. Pol. Science (Hons.) - 2nd Semester**

**Chapter Wise Reference Book  
Including Many Solved Sample Papers**

*Based on*

**C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of**

**I.G.N.O.U.**

**& Various Central, State & Other Open Universities**

*By: Ved Prakash Sharma*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

*(Publishers of Educational Books)*

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: [info@neerajbooks.com](mailto:info@neerajbooks.com)

Website: [www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

**MRP ₹ 280/-**

## Content

# भारत में राजनीतिक प्रक्रिया ( Political Process in India )

### Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)

Question Paper—June-2023 (Solved) .....	1
Question Paper—December-2022 (Solved) .....	1
Question Paper—Exam Held in July-2022 (Solved) .....	1
Sample Question Paper–1 (Solved) .....	1
Sample Question Paper–2 (Solved) .....	1

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
--------------	-----------------------------------	-------------

### राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था ( Political Parties and Party System )

1. राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्था एवं लोकतंत्र .....	1
( Political Parties, Party Systems and Democracy )	
2. भारत में राजनीतिक दल .....	11
( Political Parties in India )	
3. भारत में दलीय प्रणाली .....	23
( Party Systems in India )	

### मतदान व्यवहार का निर्धारण ( Determinants of Voting Behaviour )

4. जाति, वर्ग, जेंडर और जनजाति .....	33
( Cast, Class, Gender and Tribes )	
5. नृजातीयता, धर्म और भाषा .....	43
( Ethnicity, Religion and Language )	

### क्षेत्रीय अपेक्षाएं एवं आंदोलन ( Regional Aspirations and Movements )

6. स्वायत्ता आंदोलन ( Autonomy Movements ) .....	54
--	----

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
7.	विद्रोह ..... ( Insurgency )	67
8.	अलग राज्य की माँग के लिए आन्दोलन ..... ( Movements for Separate Statehood )	75
<b>धर्म और राजनीति ( Religion and Politics )</b>		
9.	धर्मनिरपेक्षता ..... ( Secularism )	85
10.	सांप्रदायिकता ..... ( Communalism )	95
<b>जाति और राजनीति ( Cast and Politics )</b>		
11.	जाति आधारित संगठन और राजनीतिक गठन ..... ( Caste Organizations and Political Formations )	105
12.	जाति और राजनीति ..... ( Caste and Politics )	115
<b>सकारात्मक कार्रवाही ( Affirmative Action )</b>		
13.	आरक्षण ..... ( Reservation )	126
14.	विकास ..... ( Development )	140



**Sample Preview  
of the  
Solved  
Sample Question  
Papers**

*Published by:*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

# QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

भारत में राजनीतिक प्रक्रिया  
(Political Process in India)

B.P.S.C.-104

समय : 3 घण्टे ]

[ अधिकतम अंक : 100

नोट : कुल पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रत्येक खंड से कम से कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

## अनुभाग-I

प्रश्न 1. भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्त्व की चर्चा करें।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-1, पृष्ठ-2, 'भारत में राजनीतिक दल दलीय व्यवस्था और लोकतंत्र' तथा पृष्ठ-3, प्रश्न 3

प्रश्न 2. चुनावी राजनीति में जेंडर और आदिवादी पहचानों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-4, पृष्ठ-33, 'परिचय', तथा पृष्ठ-34, 'लिंग (जेंडर), जनजाति'

प्रश्न 3. स्वायत्तता आन्दोलनों के अर्थ और लक्षणों की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-5, पृष्ठ-56, प्रश्न 1, प्रश्न 2

प्रश्न 4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त लेख लिखिए-

(क) बी.एस.पी. (BSP)

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-2, पृष्ठ-15, प्रश्न 2

(ख) चुनावों में मीडिया की भूमिका

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-4, पृष्ठ-38, प्रश्न 3

## अनुभाग-II

प्रश्न 5. किसी उदाहरण के साथ विद्रोह के लक्षणों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-7, पृष्ठ-67, 'विद्रोह क्या है?' 'भारत में विद्रोह की उत्पत्ति' तथा पृष्ठ-68, 'उत्तर-पूर्व में विद्रोह',

प्रश्न 6. हिन्दी क्षेत्र में राज्य गठन आन्दोलनों की प्रकृति की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-8, पृष्ठ-75, 'परिचय', तथा पृष्ठ-77, 'हिन्दी पट्टी राज्यों में अलग राज्य के लिए आन्दोलन'

प्रश्न 7. भारतीय राजनीति में जाति संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-11, पृष्ठ-107, प्रश्न 2, प्रश्न 3  
प्रश्न 8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त लेख लिखिए-

(क) आम आदमी पार्टी (AAP)

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-2, पृष्ठ-14, 'आम आदमी पार्टी (आप)' तथा पृष्ठ-16, प्रश्न 4

(ख) सकारात्मक क्रिया (Affirmative Action)

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-14, पृष्ठ-140, 'सकारात्मक कार्यवाही, लोकहित और विकास'

■ ■

# QUESTION PAPER

December – 2022

(Solved)

भारत में राजनीतिक प्रक्रिया  
(Political Process in India)

B.P.S.C.-104

समय : 3 घण्टे ]

[ अधिकतम अंक : 100

नोट : कुल पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रत्येक खंड से कम से कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

## अनुभाग - I

प्रश्न 1. भारत में दलीय व्यवस्था के क्रमतर विकास की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-1, पृष्ठ-2, 'भारत में दलीय प्रणाली एवं राजनीतिक दलों का विकास', पृष्ठ-3, प्रश्न 2

प्रश्न 2. चुनावी व्यवहार के निर्धारकों के रूप में जाति और वर्ग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-4, पृष्ठ-34, 'जाति', 'वर्ग'

प्रश्न 3. स्वायत्तता आंदोलनों को परिभाषित कीजिए। उदाहरणों के साथ उनके लक्षणों की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-6, पृष्ठ-56, प्रश्न 1, पृष्ठ-59, प्रश्न 1, पृष्ठ-55, 'स्वायत्तता आंदोलनों के उदाहरण'

प्रश्न 4. निम्नलिखित पर नोट लिखिए-

(क) उत्तर-पूर्व भारत में विद्रोह का उद्भव

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-7, पृष्ठ-68, 'उत्तर-पूर्व में विद्रोह'

(ख) तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-8, पृष्ठ-77, 'तेलंगाना राज्य की मांग के लिए आंदोलन'

## अनुभाग - II

प्रश्न 5. धर्मनिरपेक्षता के इर्द-गिर्द भारत में क्या वाद-विवाद है?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-9, पृष्ठ-91, प्रश्न 4

प्रश्न 6. काका कालेलकर रिपोर्ट और मंडल कमीशन की क्या सिफारिशें हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-13, पृष्ठ-130, प्रश्न 3, पृष्ठ-127, 'मंडल आयोग की रिपोर्ट'

प्रश्न 7. सकारात्मक कार्य (affirmative action) और विकास के अंतःसंबंध की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-14, पृष्ठ-140, 'सकारात्मक कार्यवाही लोकहित और विकास'

प्रश्न 8. निम्नलिखित पर नोट लिखिए-

(क) हिंदी क्षेत्र में राज्य गठन के आंदोलन

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-8, पृष्ठ-77, 'हिन्दी पट्टी राज्यों में अलग राज्य के लिए आंदोलन'

(ख) कांग्रेस व्यवस्था का पतन

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-3, पृष्ठ-24, 'कांग्रेस प्रणाली का पतन और गैर-कांग्रेसी तत्त्वों का उदय (1967-1989)'

# Sample Preview of The Chapter

*Published by:*



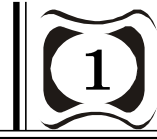
**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

# भारत में राजनीतिक प्रक्रिया ( Political Process in India )

## राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था ( Political Parties and Party System )

### राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्था एवं लोकतंत्र ( Political Parties, Party Systems and Democracy )



#### परिचय

प्रजातांत्रिक देशों में संस्थाओं की प्रमुख भूमिका होती है। राजनीतिक दल उन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें लोग विधायी निकायों में राजनीतिक दलों के नामांकित लोगों को चुनकर भेजते हैं। ये राजनीतिक दल व्यक्तियों को राजनीतिक गतिविधियों में भी सम्मिलित करते हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं को उजागर किया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी हैं। आजादी के बाद भारत में अनेक प्रकार के राजनीतिक दलों का उदय हुआ। आजादी के बाद भारत में एक दलीय व्यवस्था के प्रभुत्व का वर्चस्व रहा, जिसमें 1950 से 1960 तक कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था तथा उसके बाद की अवधि में अनेक अन्य दलों का दबदबा देखने को मिला।

इस अध्याय के अंतर्गत हम दलीय व्यवस्था और राजनीतिक दलों का अर्थ, विकास, भारत में दलीय व्यवस्था एवं राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताओं को समझना तथा राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्था एवं लोकतंत्र के बीच संबंधों की व्याख्या आदि का अध्ययन करेंगे।

#### अध्याय का विहंगावलोकन

#### राजनीतिक दलों एवं दलीय व्यवस्था का अर्थ

##### राजनीतिक दल

राजनीतिक दल को आमतौर पर जनता की एक संगठित इकाई के रूप में वर्णित किया जाता है, जो सामान्य सिद्धान्तों पर आधारित है और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इसके कुछ सामान्य लक्ष्य होते हैं। राजनीतिक दल सांविधानिक उपायों के द्वारा राजनैतिक सत्ता चाहती हैं और उसके लिए कार्य करती हैं, जिससे यह अपनी नीतियों को कार्यान्वित कर सके। यह समान सोच वाले लोगों का एक निकाय है, जिनमें लोगों में समान विचार हों।

#### दलीय व्यवस्था

दलीय व्यवस्था का अभिप्राय देश में अनेक राजनीतिक दलों से संबंधित है। संसदीय लोकतंत्र के लिए विभिन्न राजनीतिक दल आवश्यक हैं। राजनीतिक दल नागरिकों के संगठित समूह हैं, जो एकसमान विचारधारा रखते हैं। ये अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए वचनबद्ध होते हैं। राजनीतिक दल एक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं तथा हमेशा शक्ति प्राप्त करने और उसे बचाए रखने की कोशिश करते हैं। किसी देश में राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर दलीय व्यवस्था को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

1. एक-दलीय प्रणाली—यदि किसी देश में एक ही राजनीतिक दल होता है तो वह एक-दलीय प्रणाली कहलाती है, जैसे—जनवादी चीन में एक-दलीय प्रणाली है।

2. द्वि-दलीय प्रणाली—यदि किसी देश में दो दल मुख्य होते हैं और सत्ता इन्हीं दोनों के हाथों में आती-जाती रहती है, तो यह द्वि-दलीय प्रणाली कहलाती है, जैसे—संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में द्वि-दलीय प्रणाली प्रचलित है।

3. बहु-दलीय प्रणाली—बहु-दलीय प्रणाली यह एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें दो से अधिक दल मौजूद हों, जो सत्ता के लिए एक-दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। तो उसे बहु-दलीय प्रणाली कहा जाता है, जैसे—भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं। इसीलिए यहां बहु-दलीय राजनीतिक प्रणाली है।

भारत में आमतौर पर दलों की पहचान उनके प्रदर्शन का स्तर और सरकार में उनकी उपस्थिति से लगाया जा सकता है। एक से अधिक दल की उपस्थिति एवं लोकतांत्रिक और बहुलवादी समाज की विशेषता है। कई दलों की मौजूदगी भारत में एक प्रमुख दलीय प्रणाली की विशेषता रही है। 1950 से 1960 के दशक के दौर को



## 2 / NEERAJ : भारत में राजनीतिक प्रक्रिया

प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषण रजनी कोठारी ने एक दल के वर्चस्व का युग बताया। इस युग को कांग्रेस के वर्चस्व का युग कहा जाता है। एक दल के प्रभुत्व का अर्थ यह नहीं था कि भारत में सिर्फ एक ही दल था। इसका तात्पर्य है कि भारत में कांग्रेस के अतिरिक्त कई अन्य दल भी उपस्थित थे, जैसे—भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भिन्न समाजवादी दल, स्वतंत्रता दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जनसंघ इत्यादि। लेकिन इन सबमें, कांग्रेस पार्टी की सभी राज्यों में मौजूदगी थी तथा इसने केन्द्र एवं राज्यों में सरकारों का नेतृत्व भी किया था। 1960 के दशक के अंत में कांग्रेस का दबदबा कम हो गया तथा 1967 के आम चुनावों में इसे 8 राज्यों में पराजय मिली। उस दौर में कांग्रेस के अतिरिक्त कई अन्य दल भी मौजूद थे, जिन्होंने केन्द्र एवं राज्यों में मिलकर सरकार बनाई। यह भारत में बहु-दलीय प्रणाली के महत्त्व को दर्शाता है।

### भारत में दलीय प्रणाली एवं राजनीतिक दलों का विकास

स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक संविधान अपनाने के साथ 1952 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रथम आम चुनावों के दृष्टिगत एक नई दलीय व्यवस्था उभरी। स्वतंत्रता के बाद के समय में दलीय व्यवस्था विभिन्न स्थितियों अथवा चरणों से गुजरी है। आजादी के बाद भारत में तीन प्रकार की दलीय प्रणाली देखने को मिली है—एक-दलीय प्रणाली का वर्चस्व, द्वि-दलीय प्रणाली तथा बहु-प्रणाली।

#### एक दलीय व्यवस्था का प्रभुत्व

इस प्रकार के दौर को एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा जाता है क्योंकि केन्द्र और राज्यों में केवल (1956-59 में केरल का अपवाद छोड़कर) कांग्रेस दल का शासन रहा है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषण रजनी कोठारी ने इस काल को एक-दलीय वर्चस्व का काल कहा था। उन्होंने यहां तक कहा कि यह एक कांग्रेस पार्टी न होकर कांग्रेस प्रणाली थी। यह स्थिति लगभग 1967 तक कायम रही थी।

#### द्वि-दलीय

इस प्रकार की प्रणाली में दो या दो से ज्यादा दल एक साथ मिलकर चुनाव-पूर्व या चुनाव-पश्चात् गठबंधन करते हैं और सरकार बनाते हैं तथा वे न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी तय करते हैं। आमतौर पर यह दो दलों के साथ होता है जो कि आपस में ध्रुवीकरण अथवा गठबंधनों की प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसी प्रणाली को ही द्वि-ध्रुवीय प्रणाली कहा जाता है। ऐसी प्रणाली केन्द्र एवं राज्य दोनों में ही हो सकती है। ऐसी स्थिति में मुख्य राजनीतिक दल समान होता है जबकि उसके गठबंधन के सहयोगी बदल जाते हैं। भारत में इस प्रकार की प्रणाली ने ही गठबंधन की राजनीति को पनपने का अवसर दिया था।

#### बहु-दलीय एवं बहु-ध्रुवीय/दलीय/व्यवस्था

1967-75 में भारत ने बहु-दलीय व्यवस्था के उद्भव को देखा। 1967 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस आठ राज्यों में पराजित

हुई। इन राज्यों में पहली बार गैर-कांग्रेसी दलों ने संयुक्त सरकार बनाई। 1969 में कांग्रेस (ओ) तथा कांग्रेस (आर) के रूप में विघटन हुआ। परंतु 1971 के मध्यावधि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस एक बार फिर एक प्रमुख ताकत बन गई। तब आपातकाल (1975-77) का युग आया जिसे भारतीय लोकतंत्र का सर्वसत्तावादी युग कहा जाता है। बहु-दलीय व्यवस्था के उदय का प्रमुख कारण समाज में हो रहे बदलाव का भी असर था। समाज में नये मुद्दों के सृजन एवं क्षेत्रीय नेताओं का उदय भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कारण था। भारत में बहु-दलीय व्यवस्था केन्द्र एवं राज्य दोनों में स्थित है। इस तरह का गठबंधन बहु-दलीय व्यवस्था का प्रतीक है। इस प्रकार की बहु-दलीय व्यवस्था बहु-ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है।

### भारत में राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्था और लोकतंत्र

राजनीतिक दल और लोकतंत्र का घनिष्ठता का संबंध है। यह संबंध लोकतंत्र के अलग-अलग मानकों में दिखाई देता है, जैसे— नीति-निर्माण में नागरिकों की भागीदारी, उनकी एकजुटता, उनके अंदर राजनीतिक चेतना, उनके मुद्दों पर चर्चा एवं उनकी माँगों को पूर्ण करने की वचनबद्धता। लोग नीति-निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बनते हैं। उनकी भागीदारी राजनीतिक दलों द्वारा सरकार में शामिल होकर पूरी होती है। राजनीतिक दल चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गए प्रत्याशी ही नागरिकों के लिए नीति-निर्माण में मदद करते हैं। राजनीतिक दल ही ठीक प्रकार से निर्णय-निर्माण में भूमिका निभाने का उपकरण होते हैं।

लोकतंत्र में, विपक्षी दलों का यह दायित्व है कि वे सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करें। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ विधायी निकायों में भागीदारी करते हैं तथा लोकतंत्र को सशक्त करने में सहयोग करते हैं। राजनीतिक दल व्यक्तियों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में प्रमुख योगदान देते हैं। वे नागरिकों को अपनी विचारधारा से परिचित करवाते हैं।

## बोध प्रश्न

### प्रश्न 1. राजनीतिक दल एवं दल व्यवस्था को परिभाषित कीजिए।

उत्तर—राजनीतिक दल—लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल एक महत्त्वपूर्ण संस्था है, जिसके माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लिया जाता है। साधारण शब्दों में, राजनीतिक दल को आमतौर पर जनता की एक संगठित इकाई के रूप में जाना जाता है, जो सामान्य सिद्धान्तों पर आधारित है और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इसके कुछ सामान्य लक्ष्य होते हैं। राजनीतिक दल सांविधानिक उपायों के द्वारा राजनीतिक सत्ता चाहते हैं और उसके लिए कार्य करते

हैं, जिससे यह अपनी नीतियों को अमल में ला सकें। यह समान सोच वाले लोगों का एक निकाय है, जिनमें लोगों के समान विचार हों। गिलक्रिस्ट के अनुसार, राजनीतिक दल की परिभाषा है—नागरिकों का एक संगठित समूह जो समान राजनीतिक विचारों को साझा करते हैं एवं व्यक्त करते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए, सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं।'

गेटेल के अनुसार, 'एक राजनीतिक दल नागरिकों के समूह से बनता है, जो प्रायः संगठित होते हैं, जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और जो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके, सरकार को नियंत्रित करने का लक्ष्य बनाते हैं और अपनी सामान्य नीतियों का संचालन करते हैं।'

इस परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दल संगठित निकाय होते हैं और ये मूल रूप से सत्ता को पाने और उसे बचाए रखने के बारे में चिंतित रहते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताओं के रूप में, राजनीतिक दल जनता का एक संगठित समूह है। जनता का संगठित समूह सर्वमान्य नीतियों और सर्वमान्य लक्ष्यों पर विश्वास करते हैं।

**दलीय व्यवस्था**—दलीय व्यवस्था वह है जहाँ पर कई प्रकार के राजनीतिक दल उपस्थित हों। उनकी संख्या के आधार पर हम दलीय व्यवस्था का वर्गीकरण एक-दलीय, द्वि-दलीय एवं बहु-दलीय के रूप में कर सकते हैं।

भारत वर्ष में बहु-दलीय प्रणाली है, जिसमें कई राजनीतिक दल केंद्र एवं राज्यों में सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा लगी रहती हैं। भारत में समकालीन दलीय प्रणाली राष्ट्रीय एवं राज्यीय, क्षेत्रीय स्तरों पर द्वि-ध्रुवीय दलीय प्रणाली के प्रादुर्भाव की प्रत्यक्षदर्शी हैं। दो सिरों पर कार्यरत द्वि-ध्रुवीय प्रवृत्तियों का नेतृत्व कांग्रेस एवं बीजेपी द्वारा केंद्र एवं राज्यों दोनों जगह किया जाता है। राजनीतिक दल अपना-अपना आधिपत्य न दिखाकर आपस में प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी केंद्र में सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आगे आते हैं।

**प्रश्न 2. भारत में पार्टी या दलीय व्यवस्था के विकास का संक्षिप्त में विश्लेषण कीजिए।**

**उत्तर**—भारतीय दलीय व्यवस्था के विकास का प्रारम्भ 1885 में एक राजनीतिक मंच के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना औपनिवेशिक शासन के प्रत्युत्तर के रूप में तथा ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए की गई थी। स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक संविधान अपनाने के साथ 1952 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रथम आम चुनावों के दृष्टिगत एक नई दलीय व्यवस्था उभरी। स्वतंत्रता के बाद के समय में दलीय व्यवस्था तीन चरणों से होकर गुजरी है—

पहला चरण एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा जाता है, क्योंकि केन्द्र और राज्यों में केवल (1956-59 में केरल का अपवाद

छोड़कर) कांग्रेस दल का शासन रहा है। दूसरा चरण (1967-75) में भारत ने बहु-दलीय व्यवस्था के उद्भव को देखा। 1967 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस आठ राज्यों में पराजित हुई। इन राज्यों में पहली बार गैर-कांग्रेसी दलों ने संयुक्त सरकार बनाई। 1969 में कांग्रेस (ओ) तथा कांग्रेस (आर) के रूप में विघटन हुआ। परंतु 1971 के मध्यावधि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस एक बार फिर एक प्रमुख ताकत बन गई। तब आपातकाल (1975-77) का युग आया जिसे भारतीय लोकतंत्र का सर्वसत्तावादी युग कहा जाता है।

आपातकाल हटने के साथ ही कांग्रेस का प्रभुत्व भी समाप्त हो गया। 1977 के आम चुनावों में कांग्रेस को जनता पार्टी ने पराजित किया। कई राजनीतिक दलों के विलय के फलस्वरूप जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी। तीसरा चरण, 1980 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस पुनः सत्ता में लौट आई और 1989 तक सत्ता में बनी रही, 1989 के चुनावों में नेशनल फ्रंट ने भाजपा और वाम दलों के सहयोग से सरकार बनाई परंतु ये दोनों दल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाये और दसवीं लोकसभा के लिए मई-जून, 1991 में चुनाव करवाए गए।

कांग्रेस ने फिर से केन्द्र में सरकार बनाई। 1996 के आम चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई और उसे केन्द्र में सरकार बनाने का अवसर मिला। चूंकि यह निर्धारित समय में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकी इसलिए इसे त्याग-पत्र देना पड़ा। कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के बाहरी समर्थन के आधार पर बनी 13 दलों की संयुक्त मोर्चा सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। यद्यपि 1998 के चुनावों के बाद भाजपा के नेतृत्व में बनी संयुक्त सरकार को 1999 के चुनावों ने दोबारा सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया जिसने बहु-दलीय गठनबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया।

2004 के 14वें आम चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई और केन्द्र में वाम मोर्चे के समर्थन से गठबंधन की सरकार बनाई। 1989 में प्रारम्भ हुए भारतीय दलीय व्यवस्था का दौर अभी भी चल रहा है और इसे मिली-जुली अथवा गठबंधन की राजनीति का दौर कहा जाता है। कोई भी दल इस दौर में सिर्फ अपने दल के आधार पर केन्द्र में सरकार बनाने में सफल नहीं हुआ है। 2014 में भाजपा के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार बनी, उसमें भी कई दल शामिल थे। राज्यों में भी इसी प्रकार का ध्रुवीकरण देखने को मिला है। जहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों के इर्द-गिर्द गठबंधन किए गए थे।

**प्रश्न 3. राजनीतिक दलों और राजनीतिक व्यवस्था के लोकतंत्र के साथ संबंधों की व्याख्या कीजिए।**

**उत्तर**—राजनीतिक दल तथा राजनीतिक प्रणाली लोकतंत्र को सशक्त करने वाली प्रमुख संस्थाएँ हैं। इसका सकारात्मक असर यह है कि इसने समाज के निचले वर्गों को एक मंच प्रदान किया है, ताकि वे आगे आ सकें। इसने पहचान की राजनीति को भी प्रोत्साहित किया

4 / NEERAJ : भारत में राजनीतिक प्रक्रिया

है। अनेक सर्वो से पता चलता है कि इसने कमजोर वर्गों को सशक्त किया है तथा लोकतंत्र को भी मजबूत किया है। दलों की संख्या में बढ़ोत्तरी यह बताती है कि इसने राजनीतिक पहचान को और मजबूत किया है। राजनीतिक दल व्यक्तियों को एकजुट करते हैं, उनकी मांगों को अपने कार्यक्रमों और एजेंडों में शामिल करते हैं। इन्हें राजनीतिक तौर पर जागृत करते हैं तथा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए बहस करते हैं।

भारत में एक लोकतांत्रिक उथल-पुथल हुई है। ये तर्क चुनावी राजनीति के बारे में हैं जो कि और भी लोकतांत्रिकरण हो गयी है। यह सर्वविदित है कि राजनीतिक दल चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इससे यह पता चलता है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। विगत तीन दशकों की स्थिति 1950 और 1960 की अपेक्षा काफी अलग है। उस समय समाज के प्रभुत्व वर्ग का ही राजनीति वर्चस्व था, लेकिन दलीय व्यवस्था में बदलाव के कारण तथा अनेक राजनीतिक दलों के उभरने के बाद वंचित समूहों में चेतना जागृत हुई है। इसने लोकतंत्र को पिछले कुछ दशकों में और सशक्त किया है।

**बहुविकल्पीय प्रश्न**

प्रश्न 1. उग्र मानवतावादी चरण के दौरान एम.एन. राँय ने किसकी वकालत की?

- (क) एक-दलीय व्यवस्था (ख) द्वि-दलीय व्यवस्था  
(ग) दल-विहीन व्यवस्था (घ) बहु-दलीय व्यवस्था

उत्तर—(ग) दल-विहीन व्यवस्था।

प्रश्न 2. भारत की साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) स्थापित हुई—

- (क) 1964 में (ख) 1962 में  
(ग) 1961 में (घ) 1960 में

उत्तर—(क) 1964 में।

प्रश्न 3. इनमें से क्या राजनीतिक दल की एक विशेषता है?

- (क) लोगों का समूह जो अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए संगठित हैं।  
(ख) लोगों का समूह जो समान धार्मिक विचारों को साझा करते हैं।  
(ग) लोगों का समूह जिनके पास जनसाधारण से जुड़े मसलों पर सर्वमान्य विचार एवं नीतियाँ हों।  
(घ) लोगों के समूह जो चुनावी सभा में उपस्थित हों।

उत्तर—(ग) लोगों का समूह जिनके पास जनसाधारण से जुड़े मसलों पर सर्वमान्य विचार एवं नीतियाँ हों।

प्रश्न 4. हमें एक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

- (क) विधानमंडल को कानून बनाने में मदद करना  
(ख) कार्यपालिका को देश के प्रशासन में मदद करना

(ग) न्यायपालिका को न्याय प्रदान करने में मदद करना

(घ) लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने में मदद करना

उत्तर—(घ) लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने में मदद करना।

प्रश्न 5. इनमें से कौन एक लोकतंत्र नहीं है?

- (क) लीबिया (ख) इंडोनेशिया  
(ग) भारत (घ) श्रीलंका

उत्तर—(क) लीबिया।

प्रश्न 6. इनमें से कौन-सा कथन सही है?

- (क) भारत एक एक-दलीय प्रणाली है  
(ख) भारत में राजनीतिक दल स्वतंत्रता से पहले ही मौजूद थे  
(ग) भारत में राजनीतिक दलों का निर्माण स्वतंत्रता के बाद ही हुआ  
(घ) 1989 में कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत की प्राप्त नहीं हुई

उत्तर—(ख) भारत में राजनीतिक दल स्वतंत्रता से पहले ही मौजूद थे।

प्रश्न 7. एक लोकतांत्रिक प्रणाली में इनमें से क्या एक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है—

- (क) राजनीतिक दल प्रणाली में बदलाव लाने के लिए गुप्त रूप से कार्य करते हैं  
(ख) ये जनता की राय को दिशा देते हैं  
(ग) ये राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं  
(घ) यदि इन्हें विधानमंडल में बहुमत नहीं मिलता है। तो ये विपक्षी दल का गठन करते हैं

उत्तर—(क) राजनीतिक दल प्रणाली में बदलाव लाने के लिए गुप्त रूप से कार्य करते हैं।

प्रश्न 8. राष्ट्रीय स्तर पर भारत में गठबंधन सरकारों की शुरुआत कब हुई?

- (क) 1952 (ख) 1989  
(ग) 1977 (घ) 1967

उत्तर—(ख) 1989

प्रश्न 9. इनमें से कौन जम्मू एवं कश्मीर का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है?

- (क) भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (ख) नेशनल कॉन्फ्रेंस  
(ग) फॉरवर्ड ब्लॉक (घ) राष्ट्रीय जनता दल

उत्तर—(ख) नेशनल कॉन्फ्रेंस।

प्रश्न 10. शिवसेना इसमें से किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है—

- (क) महाराष्ट्र (ख) तमिलनाडु  
(ग) उत्तराखण्ड (घ) बिहार

उत्तर—(क) महाराष्ट्र।